वर्ष-15, अंक-108
पृष्ठ-8 मूल्य 2 रूपया

बिहार सिटी चीफ

सम्पूर्ण भारत मे चर्चित हिन्दी अखबार

बिहार, मंगलवार 23 जुलाई 2024

CITYCHIEFSENDMENEWS@GMAIL.COM

आज का विचार

उम्मीद रखना ऊँची उड़ानों की छांव में
ना खो जाना तुम, ठोकरों से सीख लेना
ज़रा सफर जारी रखना तुम।

सिंगल कॉलम

नीट पेपर लीक मामले की जांच में आईआईटी दिल्ली भी शामिल

नई दिल्ली। नीट-यूजी पेपर लीक मामले की जांच में अब सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली को भी शामिल कर लिया है। अदालत ने सोमवार को आदेश दिया कि आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर तीन एक्सपर्ट्स की एक कमेटी का गठन करें। यह कमेटी परीक्षा में आए एक सवाल के सही जवाब पर राय दे। दरअसल एक ऐसे सवाल का मसला भी उठा है, जिसके दो सही उत्तर माने जा रहे हैं। ऐसे में अदालत ने एक्सपर्ट्स की एक कमेटी से ही इस पर जवाब मांग लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मंगलवार को दोपहर 12 बजे तक जवाब मांगा है। इसके साथ ही कल तक के लिए सुनवाई भी टाल दी है। सोमवार को अदालत में दिलचस्प सुनवाई देखने को मिली। कोर्ट में याचियों के वकील नरेंद्र हुड्डा ने दलील दी कि एनसीईआरटी के एक सवाल के चलते 44 लोगों को टॉप रैंक मिल गई है। इस सवाल के दो जवाब सही माने जा रहे हैं। ऐसे में किसी एक जवाब को ही सही माना जाए और उस पर स्पष्टता होनी चाहिए। इसी तर्क पर अदालत ने दिल्ली आईआईटी को एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाने को कहा है। यह सवाल फिजिक्स से जुड़ा था। सुनवाई के दौरान वकील हुड्डा ने कहा कि पेपर लीक वॉट्सएप के जरिए हुआ है। इसलिए यह बिहार या झारखंड तक ही सीमित रहा, ऐसा नहीं माना जा सकता। उन्होंने सॉल्वर्स को राजस्थान से ले जाया गया। वॉट्सएप पर पेपर लीक हुआ। इसलिए इतनी गहरी साजिश है तो फिर यकीन करना मुश्किल है कि पेपर लीक पटना तक ही सीमित रहा हो। उन्होंने कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट दोबारा से एग्जाम नहीं कराना चाहता तो कम से कम क्वॉलिफाई करने वाले लोगों से दोबारा पेपर लिया जाए। वहीं एनटीए की ओर से पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने माना कि देश के 8 सेंटरों पर गलत प्रश्न पत्र बंट गया। लेकिन दोनों का लेवल एक जैसा ही था। ऐसे छात्रों की संख्या भी 3000 के करीब ही थी। ऐसे में एनटीए का यह फैसला सही है कि इन छात्रों को भी बने रहने दिया जाए। वहीं एडवोकेट हुड्डा ने कहा कि 650 से ज्याजा नंबक 241 छात्रों को मिले। इसके अलावा 241 लोगों को 550 नंबर या उससे ज्यादा मिल गए।

सिर्फ चार जोड़ों को निभानी थी शादी, हजारों जोड़ों ने विवाद की ठानी!

देहरादून। शादी बाद लड़ाई-झगड़े होने पर भले जीवनभर कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगा लेंगे, लेकिन शादी से पहले काउंसलिंग कराने नहीं जाएंगे...इस सोच से समाज को उबारने के लिए राज्य महिला आयोग ने आठ साल पहले विवाह पूर्व काउंसलिंग की जोर-शोर से पहल की थी, लेकिन अफसोस कि आज तक सिर्फ चार जोड़े ही काउंसलिंग के लिए आयोग के दफ्तर पहुंचे। विवाह पूर्व काउंसलिंग को नजरंदाज करने का नतीजा या आंकड़े ऐसे हैं कि आयोग के सामने हर साल दहेज उत्पीड़न, दहेज हत्या, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न और घरेलू हिंसा की 700 से 1000 शिकायतें पहुंच रही हैं। साथ ही दोनों पक्षों के परिजन आयोग से लेकर पुलिस स्टेशन और अदालत के चक्कर लगा रहे हैं। इसलिए महिला आयोग की कोशिश है कि लोगों को समझाया जाए कि शादी के बाद कोर्ट में एक-दूसरे के खिलाफ लड़ने से बेहतर है कि शादी से पहले काउंसलिंग के जरिए एक-दूसरे को समझा जाए। राज्य महिला आयोग का मानना है कि कई बार रिश्तों की खटास में बातचीत मिठास का काम करती है और गृहस्थी उजड़ने से बच जाती है। यदि लोग आयोग के कार्यालय नहीं आ सकते, तो उनके पास काउंसलिंग के दूसरे विकल्प भी हैं। आयोग की ही सलाह है कि लोग चाहें तो अपने नजदीक में ग्राम प्रधान, जिले के सदस्य, पारिवारिक मामलों के वकील, एनजीओ पदाधिकारी के साथ भी आपसी सामंजस्य से विवाह पूर्व कांउसिलिंग करवा सकते हैं। महिला आयोग कई मंचों से लोगों को जागरूक कर रहा है कि विवाह पूर्व काउंसलिंग करवाएं। इससे युवा पीढ़ी को उचित मार्गदर्शन मिलेगा। हिंसा और मानसिक उत्पीड़न के मामलों में कमी आएगी। आर्थिक मोर्चे पर सामंजस्य रहेगा और आमने-सामने बैठने से धोखाधड़ी की आशंका भी कम रहती है।

मोदी 3.0 का पहला बजट: आम बजट में सरकार ने खोला खजाना...

छोटे कारोबारियों को बिना गारंटी लोन

- 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री
- बिहार को 3 एक्सप्रेस वे की सौगात, कैंसर की तीन दवाएं सस्ती हुई
- मुद्रा लोन अब 20 लाख रुपए
- कस्टम ड्यूटी घटने से मोबाइल होगा सस्ता, बिहार को 41 और आंध्र को 15 हजार करोड़ का पैकेज
- पीएम आवास योजना में 3 करोड़ घर बनेंगे

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं। यह उनका लगातार सातवां बजट है। केंद्रीय मंत्रीमंडल की मंजूरी के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट संबोधन शुरू किया। वित्त मंत्री ने कहा कि इस बजट में गरीब, महिला, किसान और युवाओं पर फोकस किया गया है। जट भाषण से स्पष्ट है कि सरकार का फोकस रोजगार सृजन पर है। इसके लिए तीन योजनाओं का एलान किया गया है। पीएम आवास योजना का विस्तार किया गया है। मुद्रा लोन की सीमा बढ़ाई गई है।

पहली नौकरी वालों के लिए: 1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर, EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी।

एजुकेशन लोन के लिए: जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। लोन का 3 परसेंट तक पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई वाउचर्स लाए जाएंगे, जो हर साल एक लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे।

बिहार और आंध्रप्रदेश के लिए: आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ और बिहार को 41 हजार करोड़ रुपए की मदद। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल,ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम।

किसान के लिए: 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।

युवाओं के लिए: मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए। 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का वादा।

महिलाओं और लड़कियों के लिए: महिलाओं और लड़कियों के लिए लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान।

सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना: 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री।

मोबाइल फोन सस्ते होंगे: मोबाइल फोन और पार्टस् पर GST कम किया। मोबाइल सस्ते होंगे। एक्सपोर्ट के लिए बनने वाले लेदर गुड्स को जीएसटी से छूट।

न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़कर 75 हजार हुआ

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार किया गया। इसके अलावा 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 7 लाख रुपए तक 5 फीसदी, 7 से 10 लाख रुपए तक 10 फीसदी, 10 से 12 लाख रुपए तक 15 फीसदी। 12 से 15 लाख तक 20 फीसदी। 15 लाख से ज्यादा की सैलरी पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा।

नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ग्रामीण और शहरी इलाके में नए बिल्डिंग बॉयलाज तैयार होंगे। जमीन रजिस्ट्री के डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। लैंड रिकॉर्ड को जीआईए सिस्टम से जोड़ा जाएगा। मजदूरों के लिए ई श्रम पोर्टल शुरू किया गया है, जो वन स्टॉप सेंटर की तरह काम करेगा। श्रम सुविधा एवं समाधान पोर्टल इंडस्ट्री और ट्रेड के बीच आने वाली परेशानियों को दूर करेगा। हस्क्ष वात्सल्य अकाउंट्स की शुरुआत की जा रही है। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं।

बजट एस्टीमेट: **32.07 लाख करोड़** राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.9 फीसदी रहा है। सरकार 2026-27 में इसे कम करने की कोशिश करेगी।

टूरिज्म: निर्मला सीतारमण ने कहा कि काशी की तर्ज पर गया में विष्णु पथ मंदिर कॉरिडोर और बोध गया में महाबोधि कॉरिडोर डेवलप होंगे। ताकि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। ओडिशा में भी मंदिरों का डेवलपमेंट किया जाएगा। राजगीर बड़ा टूरिस्ट सेंटर बनेगा।

इंफ्रास्ट्रक्चर: वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में लोन के लिए 1.5 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 5 हजार नए गांवों को जोड़ा जाएगा। बिहार में बाढ़ नियंत्रण स्ट्रक्चर के लिए 11 हजार 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के कारण हर साल बाढ़ आती है। हम उसके लिए भी बाढ़ नियंत्रण स्ट्रक्चर का प्रावधान कर रहे हैं। उत्तराखंड भूस्खलन के कारण आपात स्थिति का सामना करता है। उसे भी आर्थिक मदद देंगे।

आवास: निर्मला सीतारमण ने कहा कि शहरी आवास योजना के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। 100 बड़े शहरों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति पर काम जारी है।शहरी आवास योजना के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। 1 करोड़ मकान बनाए जाएंगे। 100 बड़े शहरों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति पर काम जारी है।

एनर्जी सिक्योरिटी: निर्मला सीतारमण ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए सरकार ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत रूफ टॉप सोलर सेटअप किए जा रहे हैं। इसके लिए सब्सिडी का प्रावधान किया जा चुका है।

एमएसएमई: तरुण कैटेगरी में मुद्रा लोन का दायरा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया जा रहा है। 3 फीसदी ब्याज पर छात्रों को लोन मिलेगा। एमएसएमई क्लस्टर बढ़ाने पर सरकार का जोर है। 50 मल्टी फूड प्रोडक्ट के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। ई कॉमर्स और एक्सपोर्ट हब पीपीपी मॉडल पर बनाए जाएंगे। हमारी सरकार 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान कराएगी। ताकि वे 12 महीने में रोजगार की व्यवहारिकता को समझें। उन्हें कंपनियों के सीएसआर फंड से 5000 रुपए प्रतिमाह स्टाइपेंड भी दिया जाएगा।

रोजगार और कौशल विकास: ईपीएफओ के जरिए कुछ नई इंसेंटिव स्कीम शुरू की गई हैं। डीबीटी के जरिए 210 लाख युवाओं को फायदा मिलेगा। महिला कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सरकार नई योजना की शुरुआत की जा रही है। इस योजना में 20 लाख युवाओं को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जाएगी।

पीएम आवास योजना- 3 करोड़ नए आवास बनाए जाएंगे।

प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की जा रही है। इसमें 63 हजार गांव कवर होंगे। 2.66 करोड़ रुपए रूरल डेवलपमेंट के लिए आवंटित कर रहे हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बजट में हम 4.1 करोड़ युवाओं के रोजगार, कौशल विकास के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान कर रहे हैं। इस साल 1.48 लाख करोड़ रुपए पहले ही दे चुके हैं। इस बजट में 9 प्राथमिकताएं हैं। कृषि विकास, रोजगार और कौशल, इंफ्रास्ट्रक्चर, नेक्सट जनरेशन रिफॉर्म। सरकार सबके विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मिडिल क्लास और रोजगार पर फोकस है।

नेमप्लेट विवाद पर यूपी सरकार को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर लगाई रोक, तीन राज्य सरकारों को भेजा नोटिस

दुकान मालिकों को नाम बताने की जरूरत नहीं

नई दिल्ली। कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटलों को अपने मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने यूपी प्रशासन के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं। दुकान मालिकों को नाम बताने की जरूरत नहीं है।

दुकानदारों को सिर्फ खाने के प्रकार बताने की जरूरत है। मतलब यह कि दुकान पर सिर्फ लिखे होने की जरूरत है कि वहां मांसाहारी खाना मिल रहा है या शाकाहारी खाना। कोर्ट ने इस मामले में अदालत ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट में एनजीओ एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स द्वारा याचिका दाखिल की गई। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है, जिसे अभी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

इस तरह चली सुनवाई..........

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या यह प्रेस स्टेटमेंट था या औपचारिक आदेश था कि इन्हें प्रदर्शित किया जाना चाहिए? याचिकाकताओं के वकील ने जवाब दिया कि पहले एक प्रेस स्टेटमेंट था और फिर लोगों में आक्रोश था और वे कहते हैं कि यह स्वैच्छिक है लेकिन वे इसे सख्ती से लागू कर रहे हैं। वकील ने कहा कि कोई औपचारिक आदेश नहीं है, बल्कि पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह एक छद्म आदेश है। एक याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह ने कहा,अधिकांश लोग बहुत गरीब सब्जी और चाय की दुकान के मालिक हैं और इस तरह के आर्थिक बहिष्कार के अधीन होने पर उनकी आर्थिक मृत्यु हो जाएगी।

अभिषेक मनु सिंघवी ने दी यह दलील

अभिषेक मनु सिंघवी ने आगे कहा कि बहुत सारे शुद्ध शाकाहारी रेस्तरां हैं जो हिंदुओं द्वारा चलाए जाते हैं और उनमें मुस्लिम कर्मचारी भी हो सकते हैं, क्या मैं कह सकता हूं कि मैं वहां जाकर नहीं खाऊंगा क्योंकि खाना किसी न किसी तरह से मुस्लिमों या दलितों द्वारा छुआ जाता है? सिंघवी कहते हैं कि निर्देश में कहा गया है स्वेच्छा से (इच्छा से) लेकिन स्वेच्छा कहां है? मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा कांवड़ यात्रा मार्ग पर सभी भोजनालयों को अपने मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को इसे पूरे राज्य में बढ़ा दिया है। इस सप्ताह की शुरूआत में मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा आदेश जारी किया गया था कि कांवड़ यात्रा वाले रूट पर दुकानदार अपनी दुकान पर नेमप्लेट लगाएं ताकि कावड़ियां को पता चले कि दुकानदार का नाम क्या है।

मध्य प्रदेश के सागर में दुर्घटना

इंदौर से आ रही बस पलटी... 15 यात्री हुए घायल

सागर। सागर के मोतीनगर थाना क्षेत्र के भापेल के पास सोमवार-मंगलवार की दरमियानी रात इंदौर से सागर की ओर जा रही सवारियों से भरी बस अचानक पलट गई। हादसे में करीब 15 यात्री घायल हुए हैं। चार यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं, जो जिला अस्पताल में इलाजरत हैं।जानकारी के अनुसार इंदौर से रीवा तक चलने वाली बस क्रमांक एमपी 19 पी 2856 सागर की ओर आते समय रात करीब डेढ़ बजे भापेल में पुल के पास अनियंत्रित अचानक पलट गई। दलपतपुर चौकी क्षेत्र के खटोरा कलां निवासी प्रद्युम पिता भैयालाल अहिरवार ने बताया कि बस चालक तेज व लापरवाही पूर्वक चला रहा था, जिसके कारण यह हादसा हुआ। हादसे के समय बस में तीस से अधिक यात्री सवार थे। जानकारी के अनुसार इंदौर से रीवा तक चलने वाली बस क्रमांक एमपी 19 पी 2856 सागर की ओर आते समय रात करीब डेढ़ बजे भापेल में पुल के पास अनियंत्रित अचानक पलट गई। दलपतपुर चौकी क्षेत्र के खटोरा कलां निवासी प्रद्युम पिता भैयालाल अहिरवार ने बताया कि बस चालक तेज व लापरवाही पूर्वक चला रहा था, जिसके कारण यह हादसा हुआ। हादसे के समय बस में तीस से अधिक यात्री सवार

थे। बस के पलटते ही गहरी नींद में सो रहे यात्रियों में चीख पुकार मच गई। जैसे-तैसे यात्रियों ने बस में अपने आप को संभाला। हादसे की सूचना पुलिस और एंबुलेंस को दी गई। मौके पर मोतीनगर से एएसआई राकेश भट्ट, प्रधान आरक्षक अनिल प्रभाकर सहित अन्य पुलिस कर्मी पहुंचे और घायलों का बमुश्किल बस से बाहर निकाला। घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। घायलों को बस से निकालकर 108 एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। बस में अधिकांश यात्री मजदूर थे, जो इंदौर, भोपाल से मजदूरी कर सीधी बैढ़न तक जा रहे थे। हादसे में 23 वर्षीय प्रद्युम को दाहिने कंधे और उसकी पत्नी प्रतिमा को दाहिने घुटने, कमर में चोटें आई हैं। सागर जिले में यात्री बसों के दुर्घटनाग्रस्त होने की 15 दिन में यह पांचवीं घटना है। इसके पूर्व गढ़ाकोटा मंडी, गढ़ाकोटा के भूरेबाबा मजार के पास, बांदरी फोरलेन पर यात्री बसें हादसे का शिकार हो चुकी है, जिसमें कई यात्री घायल हुए थे।

वर्ष-15, अंक-106
पृष्ठ-8 मूल्य 2 रूपया

आज का विचार
उम्मीद रखना ऊँची उड़ानों की छांव में ना खो जाना तुम, ठोकरों से सीख लेना ज़रा सफ़र जारी रखना तुम।

बिहार सिटी चीफ

सम्पूर्ण भारत मे चर्चित हिन्दी अखबार
CITYCHIEFSENDMENEWS@GMAIL.COM
बिहार, मंगलवार 23 जुलाई 2024

बिहार में मुखिया और वार्ड सदस्यों के लिए बड़ी खुशखबरी

टेंडर पर पुनर्विचार करेगी बिहार सरकार

चन्दन कुमार चौबे । सिटी चीफ नीतीश सरकार ने 2 दिन पहले कैबिनेट बैठक में पंचायती राज विभाग को लेकर बड़ा फैसला लिया था. 15 लाख से कम की राशि के भी काम टेंडर से कराने का फैसला लिया था लेकिन अब सरकार अपने फैसले पर यू टर्न लेती दिख रही है. कैबिनेट में लिए गए फैसले से मुखिया पर लगाम लगाने की कोशिश सरकार करने वाली थी लेकिन मुखिया संघ की नाराजगी को देखते हुए पुनर्विचार करने का फैसला लिया है. इसकी जानकारी पंचायती राज विभाग के मंत्री केदार गुप्ता ने दी.

सरकार ने फैसला लिया कि छोटी-छोटी योजनाओं के लिए ग्राम पंचायत व पंचायत समिति स्तर पर 15 लाख रुपए तक की लागत वाली योजनाओं का सीमित निविदा के माध्यम से एवं अन्य सभी कार्य खुली निविदा के माध्यम से कराए जाएंगे. कैबिनेट में लिए गए फैसले का सीधा असर मुखिया और प्रमुख पर पड़ने वाला था. उनके वित्तीय अधिकार पर लगाम लग जाता. इसी के बाद मुखिया संघ ने इस पर अपनी नाराजगी जताई थी और आंदोलन की बात कही।

बाबा भुवनेश्वर नाथ धाम में उमड़ी भक्तो की भीड़

सुबह 9.30 बजे तक 75,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक

चन्दन कुमार चौबे । सिटी चीफ शिवहर, शिवहर जिले के ऐतिहासिक एवं पौराणिक धार्मिक स्थल बागमती नदी किनारे बाबा भुवनेश्वर नाथ धाम पर सावन के पहली सोमवारी को भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। देकुली धाम के मंदिर प्रबंधन समिति के सचिव संदीप भारती ने बताया है कि सुबह 9.30 तक लगभग 75,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक किया है। काफी भीड़ है लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। जिला पदाधिकारी पंकज कुमार ,पुलिस अधीक्षक अनंत कुमार राय के निर्देश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी अविनाश कुणाल ,एसडीपीओ अनिल कुमार सहित कई दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी महिला पुलिस बल स्थिति नियंत्रण को लगे हुए हैं। मंदिर प्रबंधन समिति के सचिव संदीप भारती ने बताया है कि इस बार देवकुली धाम में अरघा सिस्टम से जलाभिषेक कराया जा रहा है। इसीलिए भक्तों को बहुत सहूलियत मिली है। जबकि अनुमंडल पदाधिकारी अविनाश कुणाल, एसडीपीओ अनिल कुमार ने बताया है कि मंदिर परिसर में भक्तों की काफी लंबी लाइन है तथा भीड भी है ,लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। एन एच -104 सड़क का आवागमन भी सुचारू है। हर गतिविधि की नजर सीसीटीवी कैमरे से रखी जा रही है।

बिहार को नहीं मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा

लोकसभा में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री की दो टूक

चन्दन कुमार चौबे । सिटी चीफ नीतीश सरकार को केंद्र सरकार की ओर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग पर बड़ा झटका लगा है. केंद्र सरकार की ओर से वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में साफ कहा कि विशेष राज्य का दर्जा पाने के लिए जो नार्म्स हैं उसे सभी राज्यों को पूर करना होता है. बिहार में उसको लेकर ऐसा कुछ भी नहीं है.दरअसल, बिहार को नहीं मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा, लोकसभा में केन्द्र सरकार का जवाब लोकसभा में केन्द्र सरकार की ओर से वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जेडीयू के सवाल के जवाब में कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं है. उन्होंने कहा कि विशेष राज्य के लिए जिन प्रावधानों को पूरा करना होता है कि ऐसा कुछ भी बिहार में नहीं हैं. बता दें कि जेडीयू की ओर से सांसद रामप्रीत मंडल ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी और अपना सवाल पूछा था, जिसके जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय विकास परिषद ने विशेष राज्य श्रेणी के लिए जो मानक तय किए हैं, उनमें कठिन भौगोलिक स्थिति, कम जनसंख्या घनत्व, आदिवासी बहुल इलाका और पड़ोसी देशों के साथ सीमा क्षेत्र के साथ-साथ आर्थिक और संरचनागत पिछड़ापन को भी ध्यान में रखना होता है. कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा इसी आधार पर दिया गया है, लेकिन बिहार के संबंध में ऐसा कुछ नहीं है.

विद्यालय परीक्षा समिति पटना बिहार ने दी जानकारी

मैट्रिक इंटर में पढ़ रहे छात्रों का डमी पंजीयन कार्ड का वितरण स्कूल में 18 जुलाई से

चन्दन कुमार चौबे । सिटी चीफ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के निर्देशानुसार मैट्रिक इंटर में जो भी छात्र छात्राओं पढ़ रहें हैं उन सभी का डमी पंजीयन कार्ड स्कूल में वितरण हो रहा हैं 18 जुलाई से! मैट्रिक में जो भी छात्र छात्राओं 2025 में फाइनल परीक्षा देंगे उनका डमी पंजीयन कार्ड बिहार बोर्ड ने जारी करते हुए कहा हैं की बच्चों को डमी पंजीयन कार्ड प्राप्त कराये एवं उन में किसी प्रकार के गलती हैं तो तुरंत सुधार करवा लें! जैसे नाम. पिता का नाम. माता का नाम. जन्मतिथि. जाति.मेल फीमेल.राष्टीयता.विषय.! वर्ग आठवीं का ज्ञष्ट से नाम. माता.पिता. एवं जन्मतिथि. मिलान करें! 29 जुलाई तक सही होगा.! पुन: डमी पंजीयन कार्ड स्कूल प्रशासन को जमा करें!. सिंग्नेचर कर के एवं अभिभावक का भी सिंगनेचर करवा लें! अगर सुधार नहीं करवाते हैं तो बाद में कभी भी भविष्य में सुधार नहीं होगा. बिहार बोर्ड का निर्देश हैं!. उसी तरह इंटर के छात्र छात्राओं पहले वाला मैट्रिक के मार्कशीट से मिलान करें! विषय भी चेंज कर सकते हैं! -बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना बिहार

मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ में 1KM लंबी लाइन..50 हजार श्रद्धालु पहुंचे

सावन के पहले दिन पटना समेत बिहार के शिव मंदिर में भीड़, 72 साल बाद खास संयोग

चन्दन कुमार चौबे । सिटी चीफ मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर के गरीब स्थान मंदिर को उत्तर बिहार का बाबाधाम कहा जाता है। यहां भक्त बाबा गरीबनाथ पर जल चढ़ाने के लिए रविवार की रात से ही लंबी कतार में खड़े दिखे। आज भी यहां का नजारा अद्भुत है। सावन की पहली सोमवारी पर जलाभिषेक करने लिए भारी संख्या में श्रद्धालु और शिव भक्त जुटे। 87 किलोमीटर दूर पहलेजा से गंगा जल भरकर रविवार की रात से ही लोगों द्वारा लंबी कतार में लगकर जलाभिषेक करते हैं। इस दौरान 5 किलोमीटर दूर दूर तक हर हर महादेव की गूंज उठे रहती है। सावन की शुरुआत सोमवार से और सावन की समापन भी सोमवार से ही होगी। 22 जुलाई सावन की पहली सोमवारी है। देश सहित बिहार के हर कोने में महादेव की मंदिर में भक्तों का सुबह से ही तांता लगा हुआ है। हर शिवालय में जल चढ़ाने के लिए भक्तों की लंबी-लंबी लाइन लगी हुआ है। इस बार पूरे एक महीने में पांच सोमवारी पड़ रहा है।

गरीबनाथ मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब- सावन की पहली सोमवारी पर सुबह 6.30 बजे तक बाबा गरीबनाथ मंदिर में करीब 25 हजार शिवभक्तों ने बाबा का जलाभिषेक किया। कांवरियों का आना रविवार की रात से ही शुरू हो गया। जो सोमवार देर शाम तक जारी रहेगा। रात करीब 12 बजे से स्थानीय लोगों का आना भी शुरू हो गया। बोल बम और हर-हर महादेव के स्वर वातावरण में गूंज रहे थे। लोगों ने कतारबद्ध होकर अरघा के माध्यम से बाबा को जल चढ़ाया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हर बार की तरह ही इस बार भी पुलिस प्रशासन और मंदिर प्रबंधन की ओर से पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। मंदिर और मेला परिसर में काफी संख्या में पुरुष और महिला स्वयंसेवक तैनात हैं।

रोक के बावजूद भी बाइक से आए बम- आरडीएस कॉलेज के बाद बाइक, साइकिल या किसी भी वाहन के रोक के बावजूद बाइक बम नहीं माने। रविवार देर रात काफी बाइक सवार बम माखन साह चौक तक आए। वहां से कतार में लगकर जलाभिषेक किया।

सावन माह के हर दिन का महत्व खास गरीबनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी बाबा विनय पाठक ने बताया कि सोमवार रात तक जल चढ़ाने वाले भक्तों की संख्या 1 लाख तक पहुंच सकती है। कांवियों और स्थानीयों को मिलाकर 1 लाख तक पहुंचेगा। मेला का उद्घाटन करना प्रशासन का काम है। सावन के हर दिन का महत्व है। सिर्फ सोमवारी में पूजा मत किजिए। लोग सावन माह को सिर्फ सोमवारी में कर दिए हैं। इसे विस्तार कीजिए। सावन के हर दिन को महत्व दीजिए। हर दिन जल चढ़ाने पर इतना भीड़ भी नहीं मिलेगा।

उपमुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर गरीबनाथ मंदिर में समारोहपूर्वक किया श्रावणी मेला का उद्घाटन

मेला एप्प का हुआ लोकार्पण - मेला की सुविधाओं का श्रद्धालु लेंगे सहज रूप में प्रामाणिक जानकारी- उपमुख्यमंत्री सह जिला प्रभारी मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा के कर कमलों द्वारा बाबा गरीब नाथ मंदिर में श्रावणी मेला 2024 का दीप प्रज्वलित कर विधिवत उद्घाटन किया गया ?। समारोह को संबोधित करते हुए माननीय उपमुख्यमंत्री ने मेला में श्रद्धालुओं के लिए दी जा रही सुविधाओं की सराहना की ।साथ ही गैर- सरकारी स्तर पर दी जा रही सुविधाओं की भी सराहना करते हुए इसके विस्तारीकरण की आवश्यकता पर बल दिया। समारोह को मा. मंत्री,पंचायती राज विभाग श्री केदार प्रसाद गुप्ता एवं मा. मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग श्री दिलीप जायसवाल ने भी संबोधित किया तथा बाबा नगरी के धार्मिक, पौराणिक महत्व पर प्रकाश डाला।श्रावणी मेला के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा एप्प का लोकार्पण किया गया। एप्प के माध्यम से लाइव आरती, वर्चुअल पूजा, लाइव दर्शन, स्वास्थ्य केंद्र, नियंत्रण कक्ष, शिविर, विश्राम कक्ष, बाथरूम, फोटो गैलरी , सुविधाओं की सूची, आपातकालीन संपर्क आदि सुविधाओं की जानकारी ली जा सकती है।

डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रदर्शित कर मेला की सुविधाओं से कराया गया अवगत -समारोह में श्रावणी मेला 2024 के सफल सुचारु संचालन तथा श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु जिला प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्था के बारे में डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रदर्शित कर समारोह में लोगों को अवगत कराया गया। इस फिल्म में कांवरिया पथ ठहराव स्थल से लेकर महत्वपूर्ण चौक चौराहों तथा मंदिर के भीतर और बाहर जिला प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्था के बारे में चित्रण किया गया। फिल्म में नियंत्रण कक्ष, मेडिकल कैंप की स्थापना, ठहराव स्थल का निर्माण एवं विविध व्यवस्थाएं- पानी,बिजली, शौचालय, स्नानागार , बेड आदि की व्यवस्था का चित्रण किया गया । समारोह में नगर निगम की महापौर श्रीमती निर्मला साहु, नगर निगम की उपमहापौर श्रीमती डॉ मोनालिसा, जिला पदाधिकारी श्री सुब्रत कुमार सेन, वरीय पुलिस अधीक्षक श्री राकेश कुमार, उप विकास आयुक्त श्री आशुतोष द्विवेदी, नगर पुलिस अधीक्षक श्री अवधेश दीक्षित,अपर समाहर्ता राजस्व श्री संजीव कुमार, अपर समाहर्ता आपदा श्री मनोज कुमार सहित कई अन्य गणमान्य अतिथि, प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे।

लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो सदस्य गिरफ्तार, ऑस्ट्रिया मेड हथियार बरामद

चन्दन कुमार चौबे । सिटी चीफ लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो कुख्यातों को गोपालगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है. बताया जाता है कि कुचायकोट थाना क्षेत्र में बल्थरी चेक पोस्ट पर वाहन जांच के क्रम में राजस्थान के अजमेर जिले के पप्पू सिंह के बेटे कमल रावत को दबोचा गया. गिरफ्तार किए गए कमल के पास से पुलिस ने तलाशी के दौरान ऑस्ट्रेलिया निर्मित चार हथियार और आठ मैग्जीन बरामद किया है. कमल से पूछताछ के बाद मुजफ्फरपुर से सुनील कुमार के बेटे शांतनु शिवम को दबोचा गया.इस संदर्भ में एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि, बल्थरी चेकपोस्ट पर नियमित वाहन जांच की जा रही थी. इसी बीच एक नागालैण्ड नंबर की बस को रोककर उसकी तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान एक युवक के बैग में रखे ऑस्ट्रेलिया निर्मित विदेशी चार Glock पिस्टल और आठ मैग्जीन बरामद किया गया. हथियार बरामद होने के बाद युवक कमल सिंह को गिरफ्तार किया गया है, जो बिहार राज्य में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था. उसे मुजफ्फरपुर जाना था. फिलहाल पुलिस गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ कर रही है. गिरफ्तार अभियुक्तों के बारे में जब सघन जांच पड़ताल की गई तो दोनों अभियुक्त कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सक्रिय सदस्य निकले. फिलहाल दोनों अपराधियों से SDPO सदर के नेतृत्व में STF SOG 7, DIU की टीम के द्वारा गहन पूछताछ की गई. गैंग के अन्य सक्रिय सदस्य का पता चला है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई है.- **स्वर्ण प्रभात, एसपी, गोपालगंज**

एसपी ने बताया कि पूछताछ के क्रम में ये बात सामने आयी कि लौरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा मुजफ्फरपुर और मोतिहारी जिले में बड़ी घटना को अंजाम देने का इरादा था. पूर्व में भी गैंग के सदस्यों के द्वारा इन जिलों में रेकी की गयी है. फिलहाल अग्रतर अनुसंधान के लिए अजमेर और अन्य सम्बंधित जिलों की पुलिस से संपर्क स्थापित किया गया है. पुलिस दोनों अपराधियों को रिमांड पर लेकर अग्रतर पूछताछ करेगी.